भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *274
जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है।
20 फाल्गुन, 1947 (शक)

मोबाइल फोनों का निर्यात

***274. श्री संजय दिना पाटिल :**
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ :

क्या इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश का मोबाइल फोन निर्यात सामान्य मौसमी प्रवृत्तियों के विपरीत बढ़कर लगभग 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है और यदि हां, तो इस वृद्धि के पीछे मुख्य कारक क्या हैं तथा इसमें विशेषकर विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में मुंबई की भूमिका क्या है;

(ख) मोबाइलों के समग्र निर्यात में मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र में स्थित मोबाइल फोन विनिर्माण, असेंबली और सहायक इकाइयों का विशिष्ट योगदान क्या है;

(ग) क्या उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहनों का लाभ मुंबई के विनिर्माताओं को समान रूप से मिल रहा है या क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और मध्यम आकार की इकाइयों को प्रवेश बाधओं या प्रक्रियात्मक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मुंबई स्थित विनिर्माताओं के समक्ष आ रही चुनौतियों, जैसे कि संभार-तंत्र और पत्तन संबंधी अधिक लागत, भीड़-भाड़, कौशल कमियों, सीमित घटक पारितंत्र और अपर्याप्त औद्योगिक बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या मोबाइल फोन निर्यात में संतुलित और सतत विकास प्राप्त करने हेतु मुंबई की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए नीतिगत, बुनियादी ढांचे या निर्यात सुविधा संबंधी अतिरिक्त उपायों पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से **(ङ)** : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

मोबाइल फोनों का निर्यात के संबंध में दिनांक 11.03.2026 को लोक सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *274 के उत्तर में उल्लिखित विवरण पत्र

****

(क) से **(ङ):** भारत सरकार की नीतियां माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। हमने देश में तैयार उत्पादों के निर्माण के साथ अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स यात्रा शुरू की और फिर मॉड्यूल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। अब उप-मॉड्यूल/घटकों और इसके निर्माण में जाने वाले कच्चे माल, उपकरण और मशीनरी को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम) और आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) लॉन्च किया।

इस क्षेत्र में वृद्धि को निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है:

#	2014-15	2024-25	टिप्पणियां
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन (रु.)	~1.9 लाख करोड़	~11.3 लाख करोड़	6 गुना बढ़ा
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात (रु.)	~0.38 लाख करोड़	~3.3 लाख करोड़	8 गुना बढ़ा
मोबाइल फोनों का उत्पादन (रु.)	~0.18 लाख करोड़	~5.5 लाख करोड़	28 गुना बढ़ा
मोबाइल फोनों का निर्यात (रु.)	~0.01 लाख करोड़	~ 2 लाख करोड़	127 गुना बढ़ा

भारत ने पिछले एक दशक में मोबाइल फोन निर्माण और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। कैलेंडर वर्ष 2025 में निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं में स्मार्टफोन शीर्ष श्रेणी के रूप में उभरा है।

#	**एचएस कोड**	**मद**	**निर्यात मूल्य (यूएसडी में)**
1	85171300	स्मार्टफोन	30.13 बिलियन
2	27101944	ऑटोमोटिव डीजल ईंधन, जिसमें बायोडीजल नहीं है, मानक के अनुरूप 1460 है	16.34 बिलियन
3	71023910	तराशा गया हीरा (औद्योगिक हीरे से इतर) या अन्यथा तैयार किया गया ,न कि लगाया अथवा सेट किया गया	12.47 बिलियन

(स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय)

यह परिवर्तन सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण रणनीति के कारण संभव हुआ है। पिछले 11 वर्षों में कई पहल की गई हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई)
- आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई)

- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और अर्धचालकों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना (एसपीईसीएस)
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी और ईएमसी 2.0) योजना
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण घटक योजना (ईसीएमएस)
- सार्वजनिक खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017।
- टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाने, पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट आदि सहित कराधान में सुधार किए गए हैं।
- लागू कानूनों/विनियमों के बशर्ते इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति।

मोबाइल विनिर्माण

पिछले 11 वर्षों में, भारत ने स्वयं को मोबाइल फोन के शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक के रूप में बदल लिया है। भारत अब मोबाइल का विनिर्माण करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे देश है।

महाराष्ट्र सहित कोई भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इसके तहत लाभ उठा सकता है। विनिर्माण इकाइयों का स्थान उद्योग द्वारा तय किया जाता है।

एमएसएमई की भूमिका

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) बड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत होकर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो बड़े ओईएम और ईएमएस प्लेयर्स की क्षमताओं के पूरक हैं।

इस भूमिका को स्वीकार करते हुए, एमईआईटीवाई की योजनाएं घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एमएसएमई एकीकरण को प्रोत्साहित करती हैं। इसके आगे सरकार का यह प्रयास है कि सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं में भाग लेने के लिए एमएसएमई के लिए कोई प्रक्रियात्मक बाधाएं और प्रवेश संबंधी बाधाएं न हों।

पीएलआई योजना के तहत, 7 लाभार्थियों की विनिर्माण इकाइयां महाराष्ट्र में स्थित हैं। कुल मिलाकर इस योजना के तहत, 14 स्वीकृत आवेदक एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0

यह योजना इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करके आईटी हार्डवेयर (लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर आदि) के लिए एक मजबूत घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बना रही है। इससे आयात निर्भरता को कम करने और भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र बनाने में मदद मिली है।

3 आवेदकों की विनिर्माण इकाइयाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं और वे सभी एमएसएमई हैं।

वैश्विक कंपनियां अब भारत में लैपटॉप, सर्वर का निर्माण कर रही हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों का निर्माण

सरकार ने आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र को और सुदृढ़ करने और देश में मजबूत इलेक्ट्रॉनिक्स घटक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना (ईसीएमएस) शुरू की।

इस योजना में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी), पैसिव घटक, इलेक्ट्रो-मैकेनिकल घटक, उप-असेंबली, कैमरा मॉड्यूल, ऑप्टिकल ट्रांसीवर जैसे प्रमुख घटकों का निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत सामान शामिल है।

एमएसएमई की महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ इस योजना को अब तक उद्योग से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। 1.15 लाख करोड़ रुपये के निवेश और ~10.35 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित उत्पादन की परियोजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं।

उद्योग जगत की मजबूत प्रतिक्रिया का संज्ञान लेते हुए, बजट 2026 में सरकार ने योजना के बजटीय परिव्यय को 22,919 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये कर दिया है।

अब तक, योजना के तहत 11 राज्यों में 46 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इन आवेदनों से 54,567 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने और 50,794 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी और ईएमसी 2.0) योजना

यह योजना तैयार भूमि, उपयोगिताओं और सामान्य सुविधाओं के साथ प्लग-एंड-प्ले विनिर्माण बुनियादी ढांचा प्रदान करती है, सेटअप समय को कम करती है और उत्पादन दक्षता में वृद्धि करती है।

देश के 18 राज्यों में 30 ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) और 5 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित किए गए हैं।

अब तक, इन समूहों ने 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश जुटाया है और लगभग 90,000 रोजगार पैदा किए हैं।

ईएमसी 2.0 के तहत, 297 एकड़ क्षेत्र को शामिल करते हुए 492.85 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ रंजनगांव, पुणे में एक ग्रीनफील्ड ईएमसी को मंजूरी दी गई है। ईएमसी में अनुमानित निवेश लगभग 2000 करोड़ रुपये है।

संभाजी नगर और पुणे में क्रमशः 41 करोड़ रुपये और 67 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं के लिए दो सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) भी विकसित किए गए हैं।

कौशल विकास:

ईएसडीएम क्षेत्र में कौशल विकास को सक्षम करने के लिए, एमईआईटीवाई ने दो योजनाएं लागू कीं, अर्थात्:

- "इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में कौशल विकास के लिए चुनिंदा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता के लिए योजना" (योजना-1)
- "डिजिटल इंडिया के लिए ईएसडीएम में कौशल विकास" (योजना -2)

यह योजना 30.08.2025 को समाप्त हुई।

महाराष्ट्र राज्य में, 29,325 उम्मीदवारों को नामांकित किया गया था और 20,715 उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) भी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में विभिन्न कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य देश भर में कौशल अंतर को पाटना है।

महाराष्ट्र राज्य में, नाइलिट की अपने स्वयं के केन्द्र, अर्थात् नाइलिट औरंगाबाद के माध्यम से उपस्थिति है, जो क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है।

****